

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
विधि विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

12/11

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विधि विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 10989(भ)अनु० दिनांक 10.11.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि विधि विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 185 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह अक्टूबर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 185 योजनाओं में से 116 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 27 कार्य प्रगति में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 26 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 08 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है एवं 05 का कार्य स्थगित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य है।
- 03 योजनाओं का कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹30367.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध ₹2933.77 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।

 

